[श्री मधु दण्डवते]

दूसरी ओर वेतन में उतनी वृद्धि नहीं की जा रही है। वेतन के ढांचे के बारे में कोई समान नीति भी नहीं है। एक ओर तो कहा जा रहा है कि लोक उपक्रमों के मुनाफे और उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, दूसरी ओर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए धन नहीं है। सरकार की नीति में विरोधाभास है। रेलवे की हड़ताल रेलवे कर्मचारियों बल्कि समस्त मजदूर-वर्ग की भावनाओं, आकांक्षाओं और मांगों की प्रतीक थी परन्तु उसे कुचल दिया गया। प्रधान मंत्री को इस पर सर्वप्रथम 'दि टाइम्स" ने और तत्पश्चात "दि ईस्टर्न इकोनामिस्ट ने बधाई दी थी। एफ०आई०पी०सी०आई० के अध्यक्ष ने भी प्रधान मंत्री को बधाई दी थी।

हम इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केवल किसी एक, दो अधिकारियों को नहीं अपितु सम्पूर्ण सरकार की निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि वह त्यागपत्र दे दें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। प्रधान मंत्री जी इस पद पर 9 वर्ष पूर्व आसीन हुई थीं। 1966 से 1971 तक का समय एक संघर्ष का समय था। परन्तु 1971 से 1975 तक की कालावधि में प्रधान मंत्री ने देश में पिछड़े हुए करोड़ों लोगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं किया है। प्रधान मंत्री केवल अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रही हैं।

हमारे माननीय नेता, श्री जगजीवन राम ने गुजरात में निर्वाचनों की बात कही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सत्तारूढ़ दल काले धन और सरकारी व्यवस्था का सहारा न लें, तो वह गुजरात में जीतना तो एक तरफ रहा, सब से बड़ा अल्पसंख्यक दल भी शायद न बन सके। गत वर्ष 182 में से 140 सदस्य थे। अब वे सोच रहे हैं कि शायद 90 सीटें आ जायें। स्पष्ट है कि उनकी साख कम होती जा रही है। देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अकुशलता, भाई भतीजावाद, विधि और व्यवस्था की बिगड़ी हुई दशा से देश की हालत चिन्ताजनक हो गई है। कांग्रेस दल काले धन से और अलोकतंत्रीय ढंग अपना कर देश में चुनाव जीतता रही है।

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव सम्बन्धी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं और निर्दलीय सदस्यों को आमंत्रित किया था। सरकार इतना तक तो मानने के लिये तैयार नहीं है कि गुजरात में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें मंत्रीगण नहीं जायेंगे और सरकारी व्यवस्था का भी उपयोग नहीं किया जायेगा। गुजरात विधान सभा में संगठन कांग्रेस के 16 सदस्य थे। उम्मीदवारों की सूची निकलने से पहले ही सत्ताधारी दल ने एक सदस्य को घूस देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बावजूद वह दल परिवर्तन निषेध निधेयक की बात करता है।

लोकतन्त्र को कायम रखने के लिये कांग्रेस सरकार को देश में उचित और निर्बाध रूप से चुनाव कराने चाहियें क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ही हर बार जीतें और सरकार की बागडोर सदा आपके हाथ में ही रहे। यदि लोकतन्त्र को जीवित रखना हैं तो विपक्ष को काले धन और सिद्धान्तहीन साधनों से नहीं दबाया जाना चाहिये।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): अन्तिम वक्ता ने सत्ताधारी दल में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुजरात में दल परिवर्तन की बात का उल्लेख किया है। सम्भवतः उन्हें पता होगा कि जब

गुजरात में आन्दोलन आरम्भ हुआ था, उस समय सभी विपक्षी दलों ने एक व्यक्ति विशेष पर कई आरोप लगाये थे। हम इन आरोपों पर विचार करने के लिये तत्पर थे, यदि हमें पूरी जानकारी दी जाये। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले की जांच की गई और हमने उस व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा था क्योंकि उसके विरुद्ध ये सभी आरोप थे। अब जब उस व्यक्ति ने त्याग पत्र देकर एक नया दल बना लिया है, तो अब वही लोग उसके साथ मिल कर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।

यह देखा गया है कि जब भी मैंने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में, चाहे वह पश्चिमी एशिया था या वियतनाम था, जो भी मूल्यांकन किया उसका उपहास किया गया और उसकी आलोचना की गई। विपक्षी दल के लोग चाहे कुछ भी कहें, भारत की आवाज संसार के हर भाग में आदर से सुनी जाती है। उनके केवल कहने मात्र से सचाई बदल नहीं जायेगी। मैंने इस सभा में सभी प्रकार के आरोपों को सहन किया है परन्तु विपक्षी दलों के लोग तो कोई बात सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं। मैंने न कभी शोर मचाया है और न ही किसी वक्ता को अनावश्यक रूप से कभी टोका है।

वह समय केवल भारत के लिये ही नहीं परन्तु विश्व भर में प्रत्येक देश के लिये बहुत अधिक कठिन रहा है। यह कहना गलत है कि पूंजीवादी देशों में कठिनाईयां नहीं है। वहां भी मुद्रास्फीत है। लेकिन वहां के समाचारपत्रों और लोगों ने उन पूंजीवादी देशों को बदनाम कभी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यूरोप में किसी प्रकार की अस्थिरता और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की अस्तव्यस्तता का प्रभाव उनके देशों की अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि संसार अब अलग-थलग और छोटे-छोटे द्वीपों में नहीं बटा हुआ है। यद्यपि प्रत्येक देश की नीतियां, कठिनाइयां, समस्यायें और दृष्टिकोण अलग-अलग है तथापि दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं का प्रत्येक देश पर प्रभाव पड़ता है। यह ठीक हैं कि यूरोपीय देशों में जहां मुद्रास्फीति थी वहां पर वे बेरोजगारों की सहायता करने और वेतन में वृद्धि करने में सफल हुए हैं। मैं नहीं कहता कि हमने कभी गलतियां नहीं की हैं। यह भी दावा कभी नहीं किया गया हैं कि भारत में गरीबी को दूर करने या भारत के आर्थिक स्तरों को ऊंचा उठाने या विषमताओं को दूर करने के लिये कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जायेगा। ये हमारे उद्देश्य जरूर हैं जिन्हें हम पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

हमें कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत कम देश हैं, जिन्होंने इतनी अधिक जटिल समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया हैं। यह ठीक है कि हमारी कुछ समस्यायें हमारी भूलों और अदूरदर्शिता के कारण पैदा हुई हैं, परन्तु कुछ समस्यायें ऐसी घटनाओं के कारण उत्पन्न हो गई हैं, जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। बंगला देश का संकट और सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करना कोई मामूली बात नहीं थी। यह हमारी सफलतायें नहीं हैं तो क्या हैं ?

हमें अपने देश की तुलना अपने आसपास के देशों के साथ करनी चाहिये। हमारे देश में गरीबी है। यह कोई अचानक नहीं फैली है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि यह वह गरीबी नहीं है जो 10 या 15 वर्ष पहले थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब गरीबी और कठिनाइयों का अन्त हो गया है। चन्द ही वर्षों में इस स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता था। एक राष्ट्र के जीवन में चन्द वर्ष कोई इतना अधिक समय नहीं होता है। हमारा देश काफी समय उपनिवेशवाद का शिकार रहा। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

पश्चात् बटवारा हुआ और कई विपदाओं का सामना करना पड़ा । तत्पश्चात् आक्रमण हुए । यदि हम बड़े बड़े देशों में जायें और घूमें तो हमें पता चलेगा कि वहां भी गरीब लोग हैं ।

बार बार यह आरोप लगाये जाते हैं कि लोकतन्त्र में प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल में इस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है । क्या मैं अपनी इच्छानुसार कोई परिवर्तन करती हूं? जैसाकि अब हुआ है, मैंने अपने साथियों के साथ परामर्श किया था । ऐसा करने के लिये क्या मुझे लोगों से परामर्श करना चाहिये ? क्या ब्रिटेन में ऐसा होता है और क्या वहां पर कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है ?

मूल अधिकारों के बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता हैं । यहां बैठकें होती हैं, भाषण दिये जाते है और समाचारपत्रों और प्रकाशनों पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । हां कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की गई है, जो हिंसा पर उतारू हो गये थे । यद्यपि देश को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं, तथापि हमने किसी आन्दोलन को नहीं दबाया है ।

गुजरात में निर्वाचन पद्धति में सुधार का उल्लेख किया गया । मुझे प्रसन्नता है कि इस पर परस्पर बातचीत आरम्भ हो चुकी है और मुझे आशा है कि इससे हम कोई सर्वसम्मत मार्ग निकाल लेंगे । ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में परस्पर बातचीत तथा सहयोग से कोई हल निकल सकता है । इस दिशा में हम प्रयत्नशील रहेंगे ।

सरकार के सामने अनेकों कार्य हैं परन्तु विषमताओं को बढ़ने से रोकना और स्थायित्व लाना प्रमुख काम है जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम गड़बड़ फैला रहे हैं । भारत में हो रही घटनाओं को ध्यान से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम ऐसा कर रहे हैं ।

अनन्य कठिनाइयां होते हुए भी लोगों ने मुद्रास्फीति को रोकने में हमारे प्रयत्नों का पूरा समर्थन किया हैं । हम जानते हैं हमारे ये उपाय लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि इनसे मजदूरों, किसानों, वेतनभोगियों गृहणियों तथा प्रत्येक पर कठिनाइयों का बोझा आ पड़ा है । परन्तु इसके बावजूद भी लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से भविष्य में कठिनाइयां और बढ़ेंगी । यही कारण है कि वे वर्तमान कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हैं । हम भी सन्तुष्ट होकर तथा हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे हैं । हमें ज्ञात हैं कि मुद्रास्फीति का दबाव पूरी तरह कम नहीं हुआ है, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दल ये कदम पीछे हटा लेने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं । हम अपने प्रयत्नों में बिल्कुल ढिलाई नहीं कर सकते ।

इससे हम इंकार नहीं करते कि देश में बेरोजगारी है । परन्तु हमारी संशोधित योजना से उद्योगों में पुनः जीवन का संचार होगा और समग्र रूप में उत्पादन बढ़ेगा । इस प्रकार लोगों को विशेषकर दक्ष लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे । यदि राष्ट्र में रोजगार के नये नये अवसर निकालने हैं तो जो लोग पहले ही रोजगार में लगे हुए हैं उनको मजदूरी को बढ़ती हुई मांग को रोकना होगा । विपक्षी दल कार्मिकों को अधिक मजदूरी मांगने के लिए उकसाते हैं और साथ ही बेरोजगार लोगों के प्रति दिखावटी सहानुभूति प्रकट करते हैं ।

तस्करी और अन्य आर्थिक अपराध रोकने की दिशा में हमारे प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढिलाई आने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम विदेशी तथा भारतीय एकाधिकारियों के हितों को पूरा कर रहे हैं । लेकिन इस सदन में ही भारतीय पूंजीपतियों तथा एकाधिकारियों की वकालत करने वाले मौजूद हैं और वे अधिकांशतः विपक्षी दलों में ही बैठे हैं । उनका सतत प्रयत्न यह रहता है कि हमारे सरकारी उद्यमों की आलोचना और पूंजीवादी व्यवस्था की कार्य कुशलता की सराहना की जाये । हमारा उद्देश्य स्पष्ट हैं और हमारा इतिहास सीधा सादा है । हम अर्थ-व्यवस्था को उस तरीके से चलाना चाहते हैं जिससे कि जनता के हितों की रक्षा हो और एकाधिकारियों की शक्ति घटे ।

आपात स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । जो भी व्यक्ति विश्व की घटनाओं तथा उनके पीछे प्रवृत्तियों को समझ रहे हैं वे जानते हैं कि विश्व में आज स्थिति ही ऐसी है । हमारे प्रदेश में ही शस्त्रास्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं । हमारे समुद्री क्षेत्र में नया दबाव बढ़ रहा है । अतः ऐसे समय पर सरकार को कमजोर नहीं कया जाना चाहिए ।

हम सभी को विदित है कि हमारी सीमाओं पर अभी भी घुसपैठ तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही है । अतः हम इसे भाग्य पर नहीं छोड़ सकते । आपात की स्थिति बनाये रखने का हमारा एकमात्र उद्देश्य देश की सुरक्षा की सुदृढ़ रखना है । यह कहना एक पूर्वानुमान है कि इस स्थिति से हम लाभ उठा रहे हैं या उसके सहारे विपक्षी दलों की वैध राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा रहे हैं ।

इस सभा को विदित है कि नागालैण्ड में भ्रांत तत्वों के एक छोटे से समुदाय द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने और विदेशी शस्त्रास्त्र लाने का प्रयास किया गया है और हमारे आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप किया गया है । कोई भी सरकार देश की एकता कायम रखने और नागालैण्ड के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के अन्तर्गत अपना दायित्व निभाने से पीछे नहीं हट सकती है ।

पश्चिम बंगाल में अर्ध-फासिस्टवादी आतंक की आश्चर्यजनक बातें कही गई है । आज पश्चिम बंगाल में अर्ध या पूर्ण किसी प्रकार का आतंक नहीं है । लेकिन पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादियों के शासनकाल में अवश्य आतंक छाया हुआ था । उस समय लोग वहां पर बाहर निकलते हुए भी डरते थे । वहां की जनता के आन्दोलन से उनका शासन समाप्त हुआ है ।

आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार की भी बात आई है । हमारी सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए इतना अधिक कार्य किया है जितना कि अन्य कोई दल या सरकार नहीं कर सकती है । यह सच है कि इनके लिए जो कुछ किया गया हैं वह पर्याप्त नहीं है । सरकारी स्तर पर सर्तकता बनाये रखने की अधिक आवश्यकता है, लेकिन यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने उन पर अत्याचार किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आशा थी कि प्रधान मन्त्री मेरे उन विशेष आरोपों का उत्तर देंगी जिनमें मैंने यह स्पष्ट कहा था कि दो कम्पनियों द्वारा दल को सहायता देने के लिए उनको सीमा–शुल्क में 344.08 करोड़, रूपये की छूट दी गई है । इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत से उपदेश दिये हैं । उन्होंने दल बदल